



सेल्फी वीन निया शर्मा ने
रोका कैमरा फेस स्किन ट्रीटमेंट
के बाद लिया फैसला

पेज
07

संक्षिप्त खबरें

गोवा में संपन्न हुई ब्रिक्स ओशन एंड पोलर साइंस वर्किंग ग्रुप की 8वीं बैठक

नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त । गोवा के वास्को स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कार्यसमूह की तीन दिवसीय 8वीं बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सभी सदस्य देशों ने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा, तटीय शहरों के संरक्षण, वैश्विक महासागर अवलोकन प्रणाली को मजबूत करने और संयुक्त ध्रुवीय अनुसंधान पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा, भारत की अध्यक्षता में तटीय लचीलेपन को बढ़ावा देने, संयुक्त महासागर जैव विविधता अध्ययन करने, और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय वर्ष-5 के लिए लक्ष्य निर्धारित करने को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी। समापन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. टी. श्रीनिवास कुमार टुम्मला ने सभी देशों से इस सहयोग को ठोस शोध पहियों और युवा शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान में बदलने का आग्रह किया। इस सम्मेलन ने सदस्य देशों के बीच महासागर और ध्रुवीय विज्ञान के क्षेत्र में आपसी साझेदारी को एक नई दिशा दी है।

बिहार में विकास की बहार: 11 लाख पक्के मकान और किसानों के लिए बड़े ऐलान

पटना, यूटर्न/ 20 अगस्त । बिहार के ग्रामीण इलाकों और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान राज्य के गरीब परिवारों के लिए 11,18,937 नए पक्के आवासों और 13,427 करोड़ के भारी-भरकम वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कच्चे घरों में रहने वाले जरूरतमंदों को सुरक्षा और आत्मसम्मान देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले दो वर्षों में राज्य में कुल 24 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिन पर करीब 29,164 करोड़ खर्च हो रहे हैं। यह पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी हुई है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और सूखे से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है।

दिव्यांग युवक ने 12वीं मंजिल से लगाई छलांग

पुणे, यूटर्न/ 20 अगस्त । महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय दिव्यांग युवक की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, युवक ने कथित मानसिक प्रताड़ना, पैसों की जबरन वसूली और झूठे आरोपों से परेशान होकर अपनी जान दी। घटना से पहले रिकॉर्ड किया गया उसका वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया है। मामला भोसरी स्थित डिस्टिनेशन क्षितिज सोसायटी का है। पुलिस के मुताबिक, विनोद पेमाराम चौधरी ने 12वीं मंजिल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या की। घटना 27 जुलाई से 8 अगस्त के बीच की बताई गई है।

रेखा गुप्ता ने किया जन कौशल व स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन



» नयी दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि जन कौशल केंद्र के माध्यम से हजारों युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ने और अपने करियर को नयी दिशा देने का अवसर मिलेगा। श्रीमती गुप्ता ने आज मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योग-केन्द्रित कौशल से जोड़ना समय की सबसे बड़ी मांग है। एआई और डिजिटल तकनीकें रोजगार और उद्योगिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रही हैं।

ऐसे में युवाओं को आत्मनिर्भर और 'फ्यूचर रेडी' बनाने के लिए यह पहल एक प्रभावी सेतु का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि जन कौशल केंद्र के माध्यम से हजारों युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ने और अपने करियर को नयी दिशा देने का अवसर मिलेगा। केवल युवा ही

एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा नया विस्तार, सीएम रेखा ने मेगा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का किया शुभारंभ

दिल्ली के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अनुव्रत भवन में 'रेजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस' योजना के तहत मेगा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 200 से अधिक एमएसएमई उद्यमियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली के छोटे और मध्यम कारोबार को आधुनिक कौशल, तकनीक, वित्तीय सहायता और नए बाजारों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्यमियों के बीच बेहतर साझेदारी से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की आरएमपी योजना के तहत दिल्ली के लिए 49.74 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिक और बुजुर्ग भी यहां आकर एआई और नई तकनीकों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मोती नगर का यह जन कौशल केंद्र भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन यह उस बड़े लक्ष्य की मजबूत नींव की एक महत्वपूर्ण ईंट है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश

को संबोधित करते हुए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा और कौशल से जोड़ने का लक्ष्य सामने रखा है।

इसका उद्देश्य युवाओं को ऐसी आधुनिक क्षमताओं से लैस करना है, जिससे वे बदलती दुनिया और भविष्य की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें।

आरएसएस को डेढ़ अरब लोगों की सच्चाई जानने का अधिकार किसने दिया : राहुल

» नयी दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसने यह तय कर लिया है कि वह देश के डेढ़ अरब लोगों की सच्चाई जानता है, जबकि हर व्यक्ति अपनी सच्चाई खुद जानता है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर आरएसएस को डेढ़ अरब लोगों की सच्चाई जानने का अधिकार किसने दिया।

श्री गांधी ने जवाहर भवन में यहां गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर आयोजित 'हरा भरा स्वराज : राजीव गांधी के दृष्टिकोण को श्रद्धांजलि' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में वैचारिक लड़ाई इसी



सवाल को लेकर है कि स्वराज को अक्सर स्वतंत्रता के समान समझ लिया जाता है, जबकि इसका अर्थ खुद पर शासन करना है। यह जिम्मेदारी और सोचने का तरीका है।

कोई व्यक्ति दूसरे को स्वतंत्रता दे सकता है, लेकिन किसी दूसरे को स्वराज नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि खुद को गहराई से समझना और दुनिया के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को समझना ही स्वराज है।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि देश का हर व्यक्ति इस रास्ते पर चले। कोई व्यक्ति इंजीनियर, रसोइया, मोची या अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है तो उसे अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सरकार और देश का काम लोगों की कल्पना के दरवाजे खोलना और उन्हें अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करना है।

गन्ने से इथेनॉल बनाने के फैसले पर बोल केजरीवाल- 17 दिनों में 20 रुपए किलो महंगी हुई चीनी

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में बढ़ती चीनी की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गन्ने को इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने के फैसले का असर अब चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 17 दिनों में चीनी की कीमत करीब 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है।



‘स्कूल ठीक करो’ अभियान को लेकर मायावती ने यूपी सरकार पर साधा निशाना

» लखनऊ, यूटर्न/ 20 अगस्त

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने देशभर में यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को राज्य सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने देशभर में चल रहे 'स्कूल ठीक करो' अभियान का समर्थन किया। पूर्व सीएम मायावती ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जेन-अल्फा अर्थात् 2013 के बाद जन्मे बच्चे-बच्चियों में भी खासकर अपने थोड़े 'अच्छे दिन' की उम्मीद लगाए स्कूली छात्र-छात्राएं व उनके माता-पिता भी सुखी भविष्य हेतु अच्छी शिक्षा को लेकर हमेशा चिन्तित ही नहीं बल्कि उसके लिए लगातार काफी जद्दोजहद भी करते रहे हैं। देशभर में व विशेषकर यूपी एवं उत्तर भारत के राज्यों के स्कूलों के बदतर हालत की कड़वी जमीनी हकीकत के कारण वे लोग अति-मुखर हो गए हैं।" बसपा प्रमुख ने कहा



कि वे लोग जेन-जी अर्थात् कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के देशव्यापी 'स्कूल ठीक करो' अभियान में काफी बढ़-चढ़ कर व पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं।

हालांकि यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि जिन मासूम बच्चे-बच्चियों के हंसने-खेलने व पढ़ने-लिखने के दिन हैं, उन्हें अपनी प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा हेतु बुनियादी सुविधाओं के लिए भी सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए बढ़ाया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की नीति अपनाई। उस समय सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि इससे पेट्रोलियम आयात पर होने वाला खर्च कम होगा और देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। केजरीवाल का कहना है कि अब स्थिति ऐसी बन गई है कि चीनी की कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से चीनी आयात करने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा कि करीब 17 दिन पहले

जिस चीनी की कीमत 46 रुपए प्रति किलो बताई जा रही थी, वह अब बढ़कर लगभग 65 रुपए प्रति किलो हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत पहले चीनी का निर्यात करने वाले देशों में शामिल रहा है, लेकिन अब आयात की योजना बनाने की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने इसे सरकार की नीतियों की विफलता बताते हुए सवाल उठाया कि जब गन्ने का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल किया जाएगा तो चीनी के लिए पर्याप्त गन्ना कैसे उपलब्ध होगा।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा और भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने किया पौधरोपण

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और केन्द्रीय राज्यमंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने 'एक पेड़ मां के नाम' कैपेन के तहत गुरुवार को पीबीजी ग्राउंड में पौधे लगाए।

इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर्ष मल्होत्रा और पवन राणा के निरंतर प्रयास और लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने की पहल की सराहना की। केन्द्रीय राज्यमंत्री और दिल्ली



भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'दिल्ली में सरकार बनने के बाद से हर सेक्टर में लगातार काम और विकास हो रहा है। यह हर तरह का यानी 360 डिग्री विकास है। अगर पर्यावरण की बात करें, तो पिछली सरकारों ने पर्यावरण के नाम पर सिर्फ शोर मचाया और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए लेकिन असल में कुछ नहीं किया। सरकार बनने के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने रेखा गुप्ता के साथ मिलकर पूरे दिल्ली में 70 लाख पेड़ लगाने का कैपेन शुरू किया।' दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, 'प्रधानमंत्री द्वारा

पेड़ लगाने के लिए शुरू किए गए दूसरे कैपेन 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' की शुरूआत दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा की अध्यक्षता में की गई। अब तक इस कैपेन के तहत 50 लाख पेड़ और पौधे लगाए जा चुके हैं। इनमें से 15 लाख पेड़ और पौधे वन विभाग ने लगाए हैं।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि, 'वन्यजीवों के मामले में, हमने दिल्ली के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। यह प्लान इस बात पर केन्द्रित है कि वन्यजीवों को कैसे बचाया और बढ़ाया जाए और उनके सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए।

जनसेवा केंद्र में 80 हजार रुपए की लूट का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

» ग्रेटर नोएडा, यूटर्न/ 20 अगस्त

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने की पुलिस ने मलकपुर गांव स्थित ओम शांति जनसेवा केंद्र में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट की रकम में से 46,250 रुपए नकद, वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल और बिना नंबर की स्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओमकार पुत्र बिजेन्द्र निवासी एफएम-137, कांशीराम कॉलोनी, सेक्टर ज्यू-2, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 24 वर्ष है। पुलिस अब उसके साथी मोनू की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त 2026 को दोपहर के समय मलकपुर गांव में स्थित ओम शांति जनसेवा केंद्र पर दो नकाबपोश बदमाश मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। बदमाशों ने हथियार के बल पर जनसेवा केंद्र में मौजूद कर्मचारी को डराया-धमकाया और गल्ले में रखे करीब 80 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद सूरजपुर थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से



आरोपियों की गतिविधियों और संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी ओमकार के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके बाद पुलिस टीम ने 20 अगस्त 2026 को आईटीबीपी के सामने सर्विस रोड से उसे गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह वारदात से पहले जनसेवा केंद्र पर किसी काम से गया था। इसी दौरान उसने दुकान के मालिक को गल्ले में रुपए रखते हुए देख लिया था। इसके बाद उसने अपने साथी मोनू को इसकी जानकारी दी। दोनों ने जनसेवा केंद्र में लूट की योजना बनाई। 13 अगस्त को जब केंद्र का मालिक किसी काम से बाहर चला गया और दुकान पर उसका नौकर मौजूद था, तब दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे। दोनों ने हेलमेट लगा रखा था और अपनी शर्ट के ऊपर दूसरी शर्ट पहन रखी थी, ताकि पहचान छिपाई जा सके।

कृषि यंत्रों के अनुदान से किसानों को पराली प्रबंधन में मिलेगी बड़ी मदद: नगराधीश टीनू पोसवाल



सुपर सीडर के 74 और स्ट्रॉ बेलर के 19 लाभार्थियों का ऑनलाइन ड्रा निकाला

» निर्मल सिंह विर्क

पानीपत, यु-टर्न 20 अगस्त। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत बुधवार को जिला सचिवालय सभागार में गुरुवार को ऑनलाइन ड्रा निकाला गया। नगराधीश टीनू पोसवाल की मौजूदगी में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डीएलईसी) तथा किसानों की उपस्थिति में ड्रा की प्रक्रिया पूरी की गई।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार, कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए विभागीय पोटल पर कुल 577 आवेदन प्राप्त हुए थे। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सामान्य श्रेणी में सुपर सीडर के 74 तथा स्ट्रॉ बेलर के 19 लाभार्थी किसानों का चयन किया जाना था। इन्होंने कृषि यंत्रों के लिए पात्र आवेदकों में से ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया गया। नगराधीश टीनू पोसवाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के

साथ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ड्रा की प्रक्रिया में सभी निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों का पालन सुनिश्चित किया गया है। किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाला अनुदान न केवल उनकी आर्थिक मदद करेगा, बल्कि फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से किसान फसल अवशेषों को खेत में जलाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन कर सकेंगे। इससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक और पात्र किसानों को समयबद्ध तरीके से मिले। कृषि विभाग के सहायक अभियंता सुधीर ने बताया कि योजना के तहत आवेदक किसान अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी योजना के तहत संबंधित कृषि यंत्र पर अनुदान न लिया हो। नगराधीश ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

संक्षिप्त खबरें

20 रुपये के लेनदेन को लेकर दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या

साहिबाबाद, यूटर्न/ 20 अगस्त । शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र के विक्रम एन्क्लेव एक्सटेंशन में बुधवार दोपहर 20 रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में युवक ने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, मृतक ने कुछ समय पहले दोस्त से शराब पीने के लिए 20 रुपये उधार लिए थे। रुपये वापस मांगने पर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, विक्रम एन्क्लेव एक्सटेंशन निवासी मुश्ताक (23) कबाड़ बीनता था। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। उसकी इलाके में रहने वाले समीर से दोस्ती थी। समीर भी कबाड़ बीनता है। करीब 20 दिन पहले समीर ने मुश्ताक के कहने पर विक्रम एन्क्लेव एक्सटेंशन में किराये पर मकान लिया था। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले मुश्ताक ने समीर से शराब पीने के लिए 20 रुपये उधार लिए थे। बुधवार दोपहर करीब दो बजे समीर ने मुश्ताक से रुपये वापस मांगे। रुपये देने से मना करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद समीर ने मुश्ताक पर चाकू से कई वार कर दिए और फरार हो गया। पुलिस ने मुश्ताक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसीपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमों लगाई गई हैं।

दबंगों ने क्लब में घुसकर की मारपीट, पांच लाख लूटने का भी आरोप

कौशांबी, यूटर्न/ 20 अगस्त । वैशाली के एक मॉल स्थित बार में मंगलवार रात दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। बिल की राशि मांगने पर करीब 25-30 लोगों ने बार मालिक, मैनेजर और कर्मचारियों से मारपीट की। आरोपियों पर कर्मचारियों की सैलरी और गल्ले में रखे पांच लाख रुपये भी लूटने का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के तिलक नगर निवासी पीड़ित सुधीर जायसवाल ने थाने में दी शिकायत में आरोप लगाया कि उनके बार में लोनी के समीर और सुहान अक्सर अपने साथियों के साथ आते थे। ये लोग पार्टी के बाद बिल मांगने पर बदतमीजी करते थे। इसी कारण उन्होंने दोनों की क्लब में एंट्री बैन कर दी थी। मंगलवार रात करीब 11 बजे बार बंद होने की तैयारी चल रही थी।

तेजपाल सिंह सहरावत को मिला राष्ट्रीय सेवा सम्मान



केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया सम्मानित, गुरु रविदास जी के 650वें जन्मदिवस पर कुरुक्षेत्र में हुआ भव्य आयोजन

कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 20 अगस्त । श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की ओर से शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज जी के 650वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवा एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए तेजपाल सिंह सहरावत को केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने पर उपस्थित गणमान्य लोगों एवं समाज के सदस्यों ने तेजपाल सिंह सहरावत को बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश राठौड़, रविदास आचार्य डॉ. बनवारी लाल, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक डॉ. अनीता आर्य, पूर्व विधायक चांदराम, सूरजभान कटारिया, राष्ट्रीय महासचिव तेजपाल सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के जीवन और विचारों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि उन्होंने समानता, भाईचारे, मानवता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया।

मास्टर प्लान में सभी को अफोर्डेबल घर मुहैया कराना लक्ष्य: मनोहर लाल खट्टर

नरेला एजुकेशन हब एवं दिल्ली का इंटरनेशनल गेट वे होगा द्वारका: एलजी संधू

दिल्ली की सीमाओं के अनुरूप मास्टर प्लान: रेखा गुप्ता

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त

केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संघू एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में गुरुवार को मीडिया सेंटर में दिल्ली का मास्टर प्लान-2047 लांच कर दिया। मास्टर प्लान के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली ने बहुत बदलाव देखे हैं और नए मास्टर प्लान के बाद दिल्ली एक दम रूप में दिखेगी। एक चीज को प्रमुखता से लागू किया जाएगा।

उन्होंने 2047 तक दिल्ली की आबादी में करीब 80 लाख की वृद्धि का अनुमान लगाते हुए कहा कि सभी को मकान मुहैया कराना सरकार की प्रमुखता होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 500 एफएआर के साथ बिल्डिंग



प्लान में छूट दी गई है। मास्टर प्लान में पुराने फ्लैटों के पुनर्निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। इस मौके पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवन कुमार एवं केन्द्रीय आवासन सचिव डी तारा समेत अन्य अधिकारी भी थे। कार्यक्रम के आखिर में सवालियों के जवाब भी दिए। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान में मेट्रो के विस्तार से लेकर आरआरटीएस तक का ध्यान रखा गया

है। बिल्डिंगों की ऊंचाई पर लगे प्रतिबंधों को काफी हद तक कम किया गया है। उन्होंने इस फल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाना है। मास्टर प्लान में 40 लाख नए फ्लैट बनाने का लक्ष्य है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विशेष ध्यान रखा गया है। ट्रांजिट ऑरिएन्टेड डेवलपमेंट (डीओडी), लैंड यूज चेंज जैसे विषयों को लेकर वन विंडो प्रणाली विकसित की गई है। जिससे लोगों को काम के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। उन्होंने

बताया कि 500 वर्गमीटर वाले औद्योगिक प्लॉट के निर्माण में 15 फीसद अतिरिक्त एफ एआर देने का प्रावधान है, लेकिन इस एफएआर का इस्तेमाल कर्मचारियों के आवास के रूप में किया जाएगा। पार्किंग की अनिवार्य व्यवस्था की गयी है। लैंड पूलिंग में भी साइकिल ट्रैक पर जोर दिया गया है।

उप राज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संघू ने कहा कि मास्टर प्लान-2047 केवल विकास का मासौदा नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने वाला है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी का नरेला हब बनेगा। ऐतिहासिक सांस्कृतिक, टूरिस्ट क्षेत्र विकसित होंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर एवं उप राज्यपाल का आभार जताते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं का ध्यान रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

बड़ोदरा में 31 को होगी हिन्द मजदूर किसान पंचायत की दो दिवसीय बैठक

» सुनील बाजपेई

कानपुर, यूटर्न/ 20 अगस्त । बहु प्रतिक्षित हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक गुजरात बड़ोदरा में दि॰ 31 अगस्त व 01 सितम्बर 2026 को कराये जाने का निर्णय लिया गया है , जिसमें पूरे भारत वर्ष के केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सभी राज्यों के संगठन के अध्यक्ष, मंत्री सम्मिलित होंगे। उ॰प्र॰ लखनऊ से कानपुर के रास्ते 13 पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मण्डल 29 अगस्त को बड़ोदरा के लिए रवाना होगा।

यह जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने बताया दो दिन की कार्य समिति में भारत सरकार व प्रदेश सरकारों द्वारा लागू नये 04 लेबर कोड और रिक्त पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति, श्रम विवादों का समय से निपटारा न होने, न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन आयोग, न्यूनतम पेंशन रू० 7,500/-किये जाने और प्रत्येक श्रमिक को जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो अनिवार्यतः आयुष्यमान कार्ड के लिए 06 सदस्यों की शर्त को समाप्त किये जाने, शिक्षा व स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण किये जाने, शत प्रतिशत महंगाई सूचांक को लागू किये जाने, प्रतिवर्ष न्यूनतम वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रत्येक 05 वर्ष के भीतर अनिवार्यतः वेतन आयोग का गठन करने जैसी सभी जनहित में अति आवश्यक मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का विचार किया जायेगा।

जिला नगर आयुक्त ने समालखा नगर परिषद क्षेत्र की सभी अवैध कालोनियों व टुकड़ों का ड्रेन सर्वे कराने का केस सरकार को भेजा

ड्रेन सर्वे के बाद कालोनियों को स्वीकृत करने की रिपोर्ट भेजी जाएगी

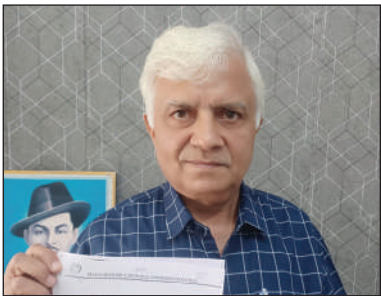
» निर्मल सिंह विर्क

पानीपत, यूटर्न/ 20 अगस्त । जिला नगर आयुक्त डॉक्टर पंकज राव ने समालखा नगर परिषद क्षेत्र की कुल 28 अवैध कालोनियों और टुकड़ों (पैच) की सूची सरकार को भेज कर यहां ड्रेन सर्वे कराने की अनुमति मांगी है। ताकि इन सभी अवैध कालोनियों का केस तैयार करके सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जा सके। यह कारवाई आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर द्वारा गत 9 जून को नगर परिषद सचिव प्रिंस मेहंदीरता को दिए गए मांग पत्र के चलते की गई है। गौरतलब है कि गत 9 जून को आरटीआई एक्टिविस्ट कॉमरेड पीपी कपूर ने नगर परिषद सचिव को बकाया सभी 28 आवासीय कालोनियों व पैच (भूखंडों) की सूची देकर इन्हें तत्काल स्वीकृत कराने का केस सरकार को भेजने की मांग की थी। नगर परिषद सचिव प्रिंस मेहंदीरता ने बताया कि अवैध कालोनियों को अप्रूव कराने का केस सरकार को भेजने के लिए पहले ड्रेन सर्वे कराना जरूरी है। जिला नगर आयुक्त पंकज राव से इन कालोनियों का पहले ड्रेन सर्वे कराने की अनुमति देने और फिर स्वीकृति के लिए केस तैयार करने के लिए उचित मार्ग दर्शन के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक को पत्र भेजा है। कपूर ने बताया कि नगर परिषद अधिकारियों की लापरवाही के कारण शहर की बहुत सारी आवासीय कालोनियों का केस सरकार को कभी अप्रूवल के लिए भेजा ही नहीं गया। जब कभी भी सरकार ने कालोनियों की सूची मांगी तो परिषद अधिकारियों ने आधा अधूरा सर्वे करके व अधूरी रिपोर्ट बना कर सरकार को भेज दी या छोटे छोटे भूखंड (पैच) छोड़ दिए गए। इस का खामियाजा यहां की पब्लिक भुगत रही है। इन क्षेत्रों

वरिष्ठ श्रमिक नेता राकेश मणि पांडेय ने बताया कि गहन चर्चा किए जाने के साथ ही श्रमिक संगठनों की मान्यता व प्रतिनिधित्व के लिए हिन्द मजदूर किसान पंचायत अपना दावा भी सरकार को पेश करेगी। उन्होंने बताया कि हिन्द मजदूर किसान पंचायत बिना समुचित हितलाभ दिये आये दिन बन्द होने वाली कम्पनियों और उनके निदेशकों द्वारा चल अचल सम्पत्ति को बेच कर भाग जाने और अन्य व्यवसाय में सामायोजित करने के खिलाफ एक मूल संघर्ष की तैयारी भी की जायेगी।

अनेक श्रमिक आंदोलन के सफल नेतृत्वकर्ता भी साबित हो चुके हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव राकेश मणि पांडेय ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि सरकारी संस्थाओं और इनके ठेकेदारों द्वारा भविष्यनिधि राज्य कर्मचारी बीमानिगम का अंशदान हड़पने, जमा न करने और एटीएम कार्ड आहरित करते हुए कर्मचारियों का वेतन भुगतान के बाद वापस लेने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य नीति बनाने के लिए सरकार को विवश किया जायेगा।

श्रमिक नेता राकेश मणि पांडेय के मुताबिक इस महत्वपूर्ण बैठक में ओवर टाइम, काम के घण्टे और अवकाश को पूर्व कानूनों के तहत लागू किये जाने और शोषण से बचाने के लिए कानूनों के क्रियान्वयन, कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने और इन हालातो के फलस्वरूप बेरोजगारी और ज्यादा न बढ़ बढ़ पाये इस पर भी गहनता से विचार किया जायेगा।



में लोग पक्की सड़कें, नालियां, सीवर, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। नगर परिषद समालखा के एरिया के अंतर्गत सर्वे में रह गई अवैध कालोनियों व छूटे हुए भूखंडों की सूची : श्री तारा एन्क्लेव कॉलोनी में गली नम्बर 13 के पीछे रेलवे लाइन तक सारा क्षेत्र, नेस्ले कंपनी के साथ लगता क्षेत्र (महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती नेस्ले रोड); पावर हाउस से लेकर श्री तारा एन्क्लेव कॉलोनी तक का एरिया, न्यू दुर्गा कॉलोनी जी.टी. रोड निरंकारी सत्संग भवन के साथ वाली गली; प्रीतम पुरा कॉलोनी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे व साथ लगता का क्षेत्र और कुच्छल के गोदाम के पास का क्षेत्र और पावर हाउस के पीछे का एरिया); चुलकाना रोड रेलवे लाइन की तरफ का क्षेत्र शास्त्री कॉलोनी; भरत नगर रेलवे लाइन पार; राजस्थान कॉलोनी रेलवे लाइन पार; राजीव कॉलोनी नारायणा रोड का क्षेत्र; स्टेट वेयर हाउस के साथ लगता एरिया (सीता राम कॉलोनी); एसएम मॉल के साथ जीटी रोड पर सीता राम कॉलोनी; एसएम मॉल के पीछे (सीता राम कॉलोनी); नगर परिषद के सामने विजय नगर का क्षेत्र व हथवाला मोड़ गांधी कॉलोनी हथवाला रोड़.

एमडब्ल्यूबी, 21 अगस्त को जगाधरी में होगा वितरण समारोह

मुकेश गर्ग मुख्यातिथि और भोपाल सिंह खदरी होंगे :सुरेंद्र मेहता

» राजेश सलूजा

हरियाणा, यूटर्न/ 20 अगस्त । मीडिया वेल-बिइंग एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) की ओर से पत्रकारों और उनके परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। संस्था की ओर से 21 अगस्त को यमुनानगर के जगाधरी रेस्ट हाउस में पत्रकारों को निःशुल्क दुर्घटना बीमा, टर्म इंश्योरेंस और कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां प्रदान की जाएंगी। कार्यक्रम में पत्रकारों को 10-10 लाख रुपये की एक्सीडेंटल तथा टर्म इंश्योरेंस और 33-33 लाख रुपये तक की सपरिवार कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

संस्था के महासचिव डॉ. सुरेंद्र मेहता ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्यातिथि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के कार्यवाहक चेयरमैन मुकेश गर्ग होंगे, जबकि मुख्यमंत्री के ग्रीवेंसिस सेल के एडवाइजर भोपाल सिंह खदरी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना एमडब्ल्यूबी के प्रमुख कल्याणकारी अभियानों में शामिल है।

डॉ. मेहता ने कहा कि एमडब्ल्यूबी पिछले



पांच वर्षों से पत्रकारों और उनके परिवारों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्य केवल पत्रकारों के पेशेवर हितों की पैरवी करना नहीं, बल्कि उनके जीवन, स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र तैयार करना भी है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में चन्द्र शेखर धरणी के नेतृत्व में एमडब्ल्यूबी पत्रकारों के प्रमुख संगठनों में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। संगठन ने विभिन्न राज्यों और जिलों में इकाइयां गठित कर पत्रकारों को एक साझा मंच प्रदान किया है। जम्मू-कश्मीर में मीर आफताब, पंजाब में सुमित खन्ना, दिल्ली में संजीव शर्मा तथा हिमाचल प्रदेश में विशाल सूद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पत्रकार कल्याण

से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।

डॉ. मेहता के अनुसार एमडब्ल्यूबी की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में पत्रकारों को बिना किसी शुल्क के बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना शामिल है। संस्था से जुड़े पत्रकारों को 10 लाख रुपये तक की टर्म इंश्योरेंस तथा 10 लाख रुपये तक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी निःशुल्क दी जा रही है। पॉलिसी के नवीनीकरण का खर्च भी संस्था द्वारा वहन किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि टर्म इंश्योरेंस पत्रकार की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहारा देती है, जबकि दुर्घटना बीमा किसी आकस्मिक हादसे की स्थिति में परिवार के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके अलावा सपरिवार कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उपचार संबंधी आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉ. मेहता ने बताया कि एमडब्ल्यूबी ने पत्रकारों के गंभीर स्वास्थ्य संकट के दौरान भी सहायता उपलब्ध कराई है। संस्था के अनुसार किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले छह पत्रकारों सहित हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कई पत्रकारों को आर्थिक मदद दी गई है।

हरियाणा के नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारियां, कार्यकताओं में खुशी : राजेश सलूजा

» हरियाणा, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

भाजपा बरवाला मंडल मीडिया प्रभारी राजेश सलूजा ने सतीश पूनिया, राज्यसभा सांसद संजय भाटिया और अरुण यादव को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

राजेश सलूजा ने कहा कि हरियाणा से जुड़े नेताओं को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व मिलना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलना उनके संगठनात्मक अनुभव और कार्यक्षमता का सम्मान है।

उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर खुशी व्यक्त



सफाई कर्मचारियों की उचित मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे : जय नारायण धाणक

अश्विनी वालिया/कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 20 अगस्त । हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के चलते शहरों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में संत श्री कबीर धाणक समाज धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र के प्रधान जय नारायण धाणक (कुराड़) ने हरियाणा सरकार से सफाई कर्मचारियों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें पूरा करने की अपील की है। जय नारायण धाणक ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों और गांवों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लंबे समय से चल रही हड़ताल के कारण जगह-जगह कूड़ा जमा हो गया है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और लोगों को पेशेानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर पर्यावरण और आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है तथा दंगरी के कारण बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने हरियाणा सरकार से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों की जायज एवं उचित मांगों पर गंभीरता से विचार कर बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए और हड़ताल को जल्द समाप्त करवाया जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके तथा शहरों में सफाई व्यवस्था सामान्य हो सके। जय नारायण धाणक ने हरियाणा की सभी धाणक समाज की सामाजिक संस्थाओं से भी अपील की कि वे अपने-अपने स्तर पर सरकार से सफाई कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने तथा हड़ताल को शीघ्र समाप्त करवाने की मांग करें।

सामाजिक मुद्दों पर 21 सदस्यीय कमेटी की मुख्यमंत्री से मुलाकात, 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी अगली बैठक

» परमिंदर सिंह

कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 20 अगस्त । कुरुक्षेत्र में 11, 12 एवं 13 जून को आयोजित सर्वजातीय खाप सम्मेलन एवं चिंतन शिविर में उठाए गए सामाजिक एवं वैवाहिक मुद्दों को लेकर 21 सदस्यीय कमेटी ने बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व देशवाल खाप के प्रधान चौधरी संजय देशवाल ने किया। बैठक में खाप प्रतिनिधियों ने



सम्मेलन में उठाए गए प्रमुख सामाजिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इनमें लिव-इन रिलेशनशिप, हिंदू मैरिज एक्ट में आवश्यक संशोधन तथा प्रेम विवाह

के मामलों में माता-पिता की सहमति से जुड़े विषय प्रमुख रहे। सम्मेलन में 36 बिरादरियों एवं विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों ने इन मुद्दों पर व्यापक चिंतन

करते हुए सरकार के समक्ष मांगें रखने के लिए 21 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया था।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि समाज में उत्पन्न हो रही विभिन्न सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार, सामाजिक संगठनों और खाप प्रतिनिधियों के बीच संवाद आवश्यक है। इन विषयों पर कानूनी एवं सामाजिक स्तर पर प्रभावी पहल किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इन सभी विषयों पर 22

अगस्त 2026 को दोपहर 2:00 बजे अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला, कुरुक्षेत्र में दोबारा विस्तृत बैठक एवं चिंतन किया जाएगा। इस बैठक में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी विशेष रूप से शामिल रहेंगे और विभिन्न खापों एवं समाज के प्रतिनिधियों की बात सुनेंगे। बैठक में सामाजिक एवं वैवाहिक कानूनों से जुड़े विषयों पर प्रतिनिधियों के सुझाव लिए जाएंगे तथा संभावित समाधान एवं आगे की कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला,

कुरुक्षेत्र के प्रधान डॉ. कृष्ण श्योकंद भी मुख्यमंत्री के साथ हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख रूप से शामिल रहे। उन्होंने कहा कि समाज से जुड़े संवेदनशील विषयों का समाधान संवाद, आपसी विचार-विमर्श तथा संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को होने वाली बैठक में विभिन्न खापों एवं समाज के प्रतिनिधियों के सुझावों को एक मंच पर रखते हुए सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा।



डॉ. वन्दना सेन

‘वन्देमातरम’ केवल दो शब्दों का उद्धोष नहीं है। यह भारत की आत्मा से निकला वह स्वर है, जिसमें मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, समर्पण, गौरव और राष्ट्रभक्ति का भाव एक साथ अभिव्यक्त होता है। जिस भूमि ने हमें जन्म दिया, जिसने हमें

राष्ट्रभक्ति जगाने का मंत्र है वन्देमातरम

अन्न, जल, वायु और जीवन प्रदान किया, उसके प्रति सम्मान प्रकट करना प्रत्येक नागरिक का स्वाभाविक और नैतिक कर्तव्य है। इसलिए ‘वन्देमातरम’ को किसी राजनीतिक दल, विचारधारा के चश्मे से देखना उसके व्यापक राष्ट्रीय अर्थ को सीमित करना होगा।

भारत की स्वतंत्रता-चेतना के इतिहास में ‘वन्देमातरम’ का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में इसके उद्धोष ने असंख्य भारतीयों के भीतर राष्ट्रभक्ति की ऐसी लौ प्रज्वलित की, जिसने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष को नई ऊर्जा प्रदान की। यह केवल गीत नहीं रहा; यह राष्ट्रीय जागरण का मंत्र बन गया था।

इसके उच्चारण मात्र से लोगों के भीतर मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का संकल्प जाग उठता था। यही कारण है कि ‘वन्देमातरम’ भारतीय राष्ट्रीय चेतना के इतिहास में एक अमिट अध्याय के रूप में दर्ज है।

आज भी जब ‘वन्देमातरम’ का स्वर वातावरण में गूँजता है तो उसके साथ देशभाव का उफान दिखाई देता है। विद्यालयों से लेकर सार्वजनिक समारोहों तक और स्वतंत्रता दिवस से लेकर राष्ट्रीय पर्वों तक, इसका उद्धोष लोगों को अपनी जड़ों और अपनी मातृभूमि से जोड़ता है। यह भाव किसी एक समुदाय, वर्ग या राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं हो सकता। भारत की विविधता में एकता

की जो विराट भावना है, ‘वन्देमातरम’ उसी भावना का सशक्त प्रतीक है।

विडंबना यह है कि जिस ‘वन्देमातरम’ को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने भी स्वीकार किया और जिसके स्वर ने स्वतंत्रता संघर्ष को ऊर्जा दी, आज उसी के प्रति कांग्रेस के कुछ नेताओं की असहजता दिखाई देती है। प्रश्न स्वाभाविक है कि जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रभाव कभी स्वतंत्रता संघर्ष के संकल्प का हिस्सा था, उसे आज राजनीतिक विवाद का विषय क्यों बनाया जा रहा है? यदि किसी राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति सम्मान व्यक्त करने में संकोच होने लगे, तो यह केवल राजनीतिक मतभेद का विषय नहीं रह

जाता, बल्कि राष्ट्रभाव की व्यापक अवधारणा पर प्रश्न खड़ा करता है।

स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में ‘वन्देमातरम’ के प्रसंग को लेकर दिखाई देने वाली असहजता ने भी अनेक प्रश्नों को जन्म दिया। राष्ट्रीय पर्वों का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को तीखा करना नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना को मजबूत करना होना चाहिए। ऐसे अवसर पर दलगत सीमाएँ पीछे छूटनी चाहिए और भारत की एकता, अखंडता तथा गौरव सर्वोपरि होना चाहिए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान के संदर्भ में उठता है। यदि ‘वन्देमातरम’ के सम्मान या उसके उद्धोष को लेकर कोई

विधिक व्यवस्था अस्तित्व में आती है, तो उसका पालन करना प्रत्येक नागरिक और संस्था का संवैधानिक दायित्व होगा। संविधान केवल राजनीतिक सुविधा के अनुसार उद्धृत करने की वस्तु नहीं है। संविधान अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी स्मृति कराता है। इसलिए जो राजनीतिक शक्तियाँ संविधान की रक्षा का दावा करती हैं, उन्हें संविधान की भावना और उसके अनुशासन का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। वस्तुतः राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक किसी दल की राजनीतिक पूँजी नहीं हैं।

पंजाब चुनाव आ रहे हैं, और जैन जेल जा रहे हैं!



संदीप शर्मा

भारतीय राजनीति में चुनावों की एक अजीब आदत है—ये सिर्फ नेताओं को ही नहीं जगाते। कभी-कभी जांच एजेंसियों में भी अचानक तेजी आ जाती है। तो, जैसे ही पंजाब एक और विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार के कथित मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टैंडर में कथित गड़बड़ी के मामले में दिल्ली सरकार की एंटी-कorrupशन

ब्रांच (ACB) ने जैन और पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने टैंडर की शर्तों में हेरफेर और पैसों के लेन-देन का आरोप लगाया है। ये गंभीर आरोप हैं और अहम बात यह है कि इन आरोपों को अभी कानूनी कसौटी पर खरा उतरना बाकी है। लेकिन जैन की प्रतिक्रिया ने इसमें राजनीतिक तड़का लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी पंजाब चुनावों से जुड़ी है। AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इस आरोप को दोहराया और कहा कि BJP एक बार फिर अपनी पार्टी को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। अब, इस टाइमिंग को समझने के लिए किसी राजनीतिक ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। जैन सिर्फ एक और AAP नेता नहीं हैं। वह पंजाब में पार्टी की संगठनात्मक जिम्मेदारियों से जुड़े रहे हैं। इसलिए उनकी गिरफ्तारी से अअद को एक साफ राजनीतिक तर्क मिल गया है: देखिए, BJP को दिल्ली में भ्रष्टाचार का पता ठीक तब चला है जब पंजाब चुनावी मैदान में उतरने वाला है। स्वाभाविक रूप से, BJP का जवाब सीधा है: भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। ठीक है। लेकिन इस तर्क में एक छोटी सी समस्या है। भारत में, भ्रष्टाचार की जांच की टाइमिंग भी उतनी ही दिलचस्प हो गई है जितना कि खुद भ्रष्टाचार।

सालों से, विपक्षी पार्टियाँ शिकायत करती रही हैं कि चुनाव नजदीक आते ही केन्द्रीय एजेंसियों में अचानक जबरदस्त उत्साह आ जाता है। BJP का हमेशा से एक ही जवाब रहा है: हमारा एजेंसियों पर कोई कंट्रोल नहीं है; वे स्वतंत्र हैं। बेशक वे स्वतंत्र हैं। और एक और अजीब संयोग यह है कि अक्सर एजेंसियों की राजनीतिक टाइमिंग भी बहुत सटीक होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जैन बेगुनाह हैं। और न ही उनकी गिरफ्तारी का मतलब यह है कि मामला अपने आप राजनीतिक रूप से प्रेरित हो गया। अगर अउड के पास सबूत हैं कि पब्लिक टैंडर में हेरफेर की गई और पैसे का अवैध लेन-देन हुआ, तो जैन और इसमें शामिल सभी लोगों को कानून का सामना करना चाहिए। राजनीति की वजह से जांच से कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन BJP को विश्वसनीयता का बुनियादी सिद्धांत भी समझना चाहिए: जब आप बार-बार चुनावों के आस-पास विपक्षी नेताओं की जांच करते हैं, तो लोगों को यह पूछने का हक है कि क्या कैलेंडर भी आपके साथ मिलकर जांच कर रहा है। इस बीच, अअद को भ्रष्टाचार के हर आरोप को साजिश बताने से बचना चाहिए। अगर मामला कमजोर है, तो सबूतों को उसे सामने आने दें। अगर मामला मजबूत है, तो अदालतों को दोषी साबित करने दें। पंजाब के वोटों की राय अलग हो सकती है। शायद जैन मामले की असली परीक्षा यह नहीं है कि क्या यह पंजाब चुनाव से पहले सुर्खियां बटोरता है। असली परीक्षा यह है कि क्या वोटों की गिनती के बाद भी यह मामला उतना ही जरूरी—और उतना ही मजबूत—बना रहता है। अगर ऐसा होता है, तो BJP दावा कर सकती है कि यह भ्रष्टाचार का मामला था। अगर ऐसा नहीं होता है, तो केजरीवाल आखिरकार कह सकते हैं: देखिए, मैंने कहा था न—चुनाव ही असली आरोपी था।

झुर्रियों में छिपा अनुभव समाज की सबसे अनमोल विरासत

योगेश कुमार गोयल



केंद्र सरकार की अटल वयो अयुध योजना का उद्देश्य भी वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास एवं देखभाल सेवाएं, राज्य कार्ययोजनाएं, सहायक उपकरण तथा सक्रिय एवं स्वस्थ वृद्धावस्था से जुड़े विभिन्न घटक शामिल हैं। भारत में 2026 तक 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी लगभग 17.3 करोड़ पहुंचने का अनुमान लगाया है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृद्धावस्था में नियमित आय का स्रोत समाप्त होने अथवा कम होने से जीवनयापन कठिन हो सकता है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं महत्वपूर्ण सहायता बनती हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन जैसी व्यवस्थाएं जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं।

किसी भी परिवार की वास्तविक समृद्धि केवल उसकी आर्थिक संपन्नता से नहीं बल्कि उसके बुजुर्गों की मौजूदगी, अनुभव और आशीर्वाद से मापी जाती है। उम्र के साथ शरीर भले ही कमजोर हो जाए लेकिन जीवन के दशकों से अर्जित अनुभव, धैर्य, दूरदृष्टि और रिश्तों को संभालने की क्षमता किसी अमूल्य धरोहर से कम नहीं होती। वरिष्ठ नागरिक केवल परिवार के अतीत के साक्षी नहीं बल्कि वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए अनुभव की जीवंत पाठशाला होते हैं। इसी भाव को केंद्र में रखकर 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में बुजुर्गों के सम्मान, उनकी समस्याओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का अवसर माना जाता है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनल्ड रीगन ने 19 अगस्त 1988 को एक घोषणा पर हस्ताक्षर कर 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मान्यता दी थी।

वृद्धावस्था जीवन का वह पड़ाव है, जिसमें व्यक्ति को सबसे अधिक जरूरत होती है सम्मान की, अपनत्व की, सुरक्षा की और यह महसूस करने की कि समाज में उसकी उपयोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है। आधुनिक जीवनशैली, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, रोजगार के लिए पलायन और संयुक्त परिवारों के कमजोर पड़ते ढांचे ने बुजुर्गों के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। कई वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक बीमारियों के साथ अकेलेपन, आर्थिक असुरक्षा, डिजिटल दुनिया से दूरी, सामाजिक अलगाव और भावनात्मक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र भी बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास, परिवहन, परिवार और सामाजिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों को महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती मानता है। दुनिया में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 1980 के लगभग 26 करोड़ से बढ़कर 2021 में 76.1 करोड़ हो गई थी और 2050 तक वैश्विक आबादी में उनका हिस्सा लगभग 17 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है। भारत के संदर्भ में यह चुनौती और अधिक महत्वपूर्ण है। देश में जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही



है। ऐसे में वृद्धावस्था को बोझ की तरह देखने के बजाय इसे जीवन के सक्रिय, सम्मानजनक और उत्पादक चरण के रूप में स्वीकार करना होगा। केंद्र सरकार की अटल वयो अयुध योजना का उद्देश्य भी वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास एवं देखभाल सेवाएं, राज्य कार्ययोजनाएं, सहायक उपकरण तथा सक्रिय एवं स्वस्थ वृद्धावस्था से जुड़े विभिन्न घटक शामिल हैं। भारत में 2026 तक 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी लगभग 17.3 करोड़ पहुंचने का अनुमान लगाया है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृद्धावस्था में नियमित आय का स्रोत समाप्त होने अथवा कम होने से जीवनयापन कठिन हो सकता है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं महत्वपूर्ण सहायता बनती हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन जैसी व्यवस्थाएं जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं। इसके साथ ही पहुंच, वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल लेन-देन में सुरक्षित प्रशिक्षण भी आज की आवश्यकता है क्योंकि साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों में वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हैं। स्वास्थ्य वरिष्ठ नागरिकों की सबसे बड़ी जरूरतों में शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग, गठिया, दृष्टि संबंधी समस्याएं, सुनने की क्षमता में कमी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का जोखिम बढ़ सकता है। भारत सरकार का ‘नेशनल प्रोग्राम फॉर हैल्थ केयर ऑफ द एल्डरली’ वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती और समग्र स्वास्थ्य

सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम, रोगों का निदान एवं उपचार, पुनर्वास, डे-केयर तथा जरूरत के अनुसार घर पर देखभाल जैसी सेवाओं की परिकल्पना की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए केवल चिकित्सा सुविधा पर्याप्त नहीं है, उन्हें सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा भी चाहिए। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, आर्थिक शोषण और अकेलापन ऐसी समस्याएं हैं, जिन पर परिवार और समाज दोनों को गंभीरता से विचार करना होगा। किसी बुजुर्ग की बात को इसलिए खारिज कर देना कि वे पुराने विचारों के हैं, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। नई पीढ़ी और वरिष्ठ पीढ़ी के बीच संवाद की कमी अनेक पारिवारिक तनावों को जन्म देती है। आवश्यकता इस बात की है कि घरों में बुजुर्गों को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए, उनकी राय सुनी जाए और उनके अनुभवों को सम्मान दिया जाए। डिजिटल युग में वरिष्ठ नागरिकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना भी जरूरी है। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी पोर्टल और वीडियो कॉल जैसी सुविधाएं उनके जीवन को आसान बना सकती हैं लेकिन डिजिटल जानकारी के अभाव में वे ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए परिवार के युवा सदस्यों को चाहिए कि वे बुजुर्गों को तकनीक से दूर रखने के बजाय उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार सिखाएं, जैसे ओटीपी साझा न करना, बैंक संबंधी जानकारी किसी को न देना और संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत संबंधित संस्था को देना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुजुर्गों की देखभाल को केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं बनाया जा सकता।

नए पिक्सल 11 सीरीज के साथ भारत पर बड़ा दांव लगा रहा गूगल, स्थानीय विनिर्माण और एआई पर बड़ा फोकस

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त

अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल ने भारत में अपनी नई पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च करते हुए देश को अपने वैश्विक विस्तार और विनिर्माण रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के सकेत दिए हैं। ऐसे समय में जब रिपोर्ट्स में गूगल द्वारा चीन से पिक्सल स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच और वायरलेस ईयरबड्स के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से बाहर स्थानांतरित करने की बात कही जा रही है, भारत कंपनी के लिए एक प्रमुख विनिर्माण और विकास केंद्र के रूप में उभर रहा है।

विश्लेषकों के अनुसार, भारत सरकार की स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों और तेजी से विकसित हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र ने गूगल जैसे वैश्विक



प्रौद्योगिकी ब्रांडों को आकर्षित किया है। गूगल पहले ही भारत में चुनिंदा पिक्सल स्मार्टफोन मॉडल का उत्पादन शुरू कर चुका है। अगस्त 2024 में पिक्सल 8 के साथ स्थानीय उत्पादन की शुरुआत हुई थी, और इसके बाद कंपनी ने देश में

अपनी विनिर्माण गतिविधियों का विस्तार किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल ने नई पीढ़ी के पिक्सल उपकरणों के निर्माण के लिए फॉक्सकॉन जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी की है।

इससे भारत को वैश्विक स्मार्टफोन आपूर्ति शृंखला में और मजबूत स्थान मिलने की उम्मीद है।

गूगल इंडिया में डिवाइसेज एंड सर्विसेज के प्रबंध निदेशक मितुल शाह ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य हमेशा उपभोक्ताओं की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना रहा है, ताकि वे तकनीक का सहज अनुभव प्राप्त कर सकें।

उन्होंने कहा, 'हमारा ध्यान भारतीय उपभोक्ताओं की दैनिक जरूरतों से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। पिक्सल 11 शृंखला इसी सोच का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें विशेष रूप से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर हार्डवेयर, एआई और दीर्घकालिक उपयोगिता को एक साथ जोड़ा गया है।'

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने जुलाई 2026 में किया शानदार प्रदर्शन

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जुलाई 2026 में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स, सभी कैटेगरी में जबरदस्त वार्षिक वृद्धि देखी गई है। जुलाई में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 34.3 प्रतिशत बढ़कर 4,57,810 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 3,40,772 यूनिट था। थ्री-व्हीलर्स की बिक्री में भी 33.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जिससे यह 92,560 यूनिट तक पहुंच गई, और टू-व्हीलर्स की बिक्री 22.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 19,23,483 यूनिट पर पहुंच गई। इन सभी कैटेगरी में कुल उत्पादन 33,70,958 यूनिट दर्ज किया गया। सियाम के विस्तृत आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में दो-पहिया वाहनों की घरेलू बिक्री बढ़कर 19,23,483 यूनिट हो गई, जिसमें स्कूटर की बिक्री 23.7 प्रतिशत बढ़कर 7,98,190 यूनिट और मोटरसाइकिल की बिक्री 20.7 प्रतिशत बढ़कर 10,74,796 यूनिट रही। मोपेड की बिक्री में 48.6 प्रतिशत का बड़ा इजाफा हुआ और यह 50,497 यूनिट पर पहुंच गई। इसी तरह, थ्री-व्हीलर्स की बिक्री में भी पैसेंजर कैरियर, गुड्स कैरियर, ई-रिक्शा और ई-कार्ट सभी में वृद्धि देखी गई।

ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत

मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सहयोग पर होगा फोकस



» नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

भारत शुक्रवार को 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी), डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और मजबूत डिजिटल अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) को लेकर सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। यह बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित की जा रही है।

भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण' विषय को चुना है। वहीं

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र की थीम 'लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन (आईसीटी)' रखी गई है।

गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये प्राथमिकताएं समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ डिजिटल विकास को बढ़ावा देने तथा ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। यह मंच ब्रिक्स देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य की संचार प्रणालियों, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और

समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।

बैठक में डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने और विभिन्न देशों के सफल अनुभवों को साझा करने पर भी जोर दिया जाएगा। भारत का मानना है कि इन पहलों का लाभ केवल ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक वैश्विक दक्षिण के देशों को भी मिलेगा।

भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहयोग को विशेष प्राथमिकता दी है। इस दिशा में मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भविष्य की नेटवर्क प्रौद्योगिकियां, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवाचार और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

दूरसंचार विभाग ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहयोग कार्य समूह के तहत चल रही चर्चाओं का नेतृत्व कर रहा है, जिनमें प्रस्तावित ब्रिक्स क्षमता निर्माण केंद्रों की स्थापना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ाने जैसे विषय शामिल हैं। यह बैठक वर्ष 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक के निर्णयों और सहयोग के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम करेगी।

रुपया 17 पैसे मजबूत होकर 95.56 प्रति डॉलर पर खुला

मुंबई, यूटर्न/ 20 अगस्त । अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.57 प्रति डॉलर पर खुला। इसके बाद 95.56 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 17 पैसे की बढ़त है। रुपया बुधवार को लगभग स्थिर कारोबार करता हुआ एक पैसे की मामूली बढ़त के साथ 95.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.82 पर आ गया। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला है।

डॉलर में कमजोरी से सोने और चांदी में जोरदार उछाल

नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त । सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कमजोर होते डॉलर, वैश्विक बॉन्ड यील्ड में नरमी और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने बहुमूल्य धातुओं को मजबूत समर्थन दिया। घरेलू एमसीएक्स और अंतरराष्ट्रीय कॉमेक्स बाजारों में सोने-चांदी की शुरुआत तेजी के साथ हुई। घरेलू मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी दोनों के वायदा भाव में मजबूती दर्ज की गई। खबर लिखे जाने तक सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 283 रुपये की तेजी के साथ 1,58,279 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। यह 1,58,008 रुपये पर खुला था और दिन के दौरान 1,58,300 रुपये का उच्च स्तर छुआ। इस साल सोने ने 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम का सर्वोच्च स्तर छुआ था। वहीं चांदी का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 3,513 रुपये की जोरदार उछाल के साथ 2,40,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर था।

संक्षिप्त खबरें

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ने स्थापित किया नया कीर्तिमान

नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त । मारुति सुजुकी के दबदबे के साथ उसकी गाड़ियों का जलवा विदेशी बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कंपनी की लोकप्रिय कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। निर्यात के मामले में इस गाड़ी ने 2 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है, और यह उपलब्धि निर्यात शुरू होने के महज 38 महीनों से भी कम समय में हासिल की गई है। इसके साथ ही, फ्रोंक्स भारत से सबसे तेजी से 2 लाख एक्सपोर्ट का आंकड़ा छूने वाली देश की पहली एसयूवी बन गई है, जो भारतीय इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता का प्रमाण है। मारुति सुजुकी ने जून 2023 में फ्रोंक्स का निर्यात शुरू किया था, और बहुत जल्द ही इस मेड-इन-इंडिया एसयूवी ने दुनिया भर के लगभग 90 देशों में अपनी अलग पहचान बना ली। घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन गुजरात के हंसलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जा रहा है। फ्रोंक्स की निर्यात वृद्धि में इसकी रफ्तार बेहद दिलचस्प रही है; जहां पहले 1 लाख यूनिट्स के निर्यात में लगभग 25 महीने लगे, वहीं अगले 1 लाख यूनिट्स सिर्फ 13 महीनों में निर्यात कर दिए गए, जो वैश्विक बाजार में इसकी बढ़ती मांग को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से ही मारुति सुजुकी फ्रोंक्स भारत की सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली पैसेंजर व्हीकल बनी हुई है, जिसने कंपनी की कुल विदेशी बिक्री को बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।

टेक्नो ने लांच किया पोवा 8 प्रो 5जी

नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त । भारतीय बाजार में टेक्नो ने अपना नया प्रीमियम गेमिंग स्मार्टफोन पोवा 8 प्रो 5जी लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में गेमिंग के साथ-साथ एक शानदार डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और बेहतर कैमरा का संगम मिलता है। यह फोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7000 सीरीज के चिपसेट से लैस है, जो दमदार परफॉर्मेंस का वादा करता है। पोवा 8 प्रो 5जी में 6500 एमएएच की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे यूजर्स को लंबे समय तक बिना चार्जिंग की चिंता किए गेम खेलने और फोन इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का ऑटो-फोकस कैमरा शामिल है। पोवा 8 प्रो 5जी को भारत में दो वेरिएंट में पेश किया गया है: 8जीबी रैम + 256जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत रुपये 49,999 है, जबकि 12जीबी रैम + 512जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत रुपये 54,999 है।

आईफोन लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

अपनी आईफोन लॉन्च रणनीति में ऐपल कंपनी एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। रणनीति के तहत सितंबर 2026 में केवल आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल ही पेश किए जा सकते हैं। कंपनी बेस आईफोन 18 मॉडल को 2027 की शुरुआत तक टाल सकती है, जिससे आईफोन 18 प्रो इस साल ऐपल का नया 'डिफॉल्ट' मॉडल बन जाएगा।

इसका मतलब यह होगा कि सितंबर में नया आईफोन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए आईफोन 18 प्रो सबसे किफायती विकल्प होगा। यह बदलाव ऐपल की पारंपरिक रणनीति से अलग है, जहाँ कंपनी पिछले कई वर्षों से सितंबर में सभी नए आईफोन मॉडल एक साथ लॉन्च करती रही है। ताजा रिपोर्ट्स और ऐपल सप्लायर पेगाट्रॉन के संकेतों के मुताबिक,



सितंबर 2026 में आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और कंपनी का पहला फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, बेस आईफोन 18, आईफोन 18ई और आईफोन एयर 2 को स्प्रिंग 2027 में पेश किया जा सकता है। इस तरह, मार्च 2027 तक ऐपल के नए आईफोन लाइनअप में कुल छह नए मॉडल शामिल हो सकते हैं।

आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को शादी के लिए किया प्रपोज

भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और अभिनेता पवन सिंह की दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। दोनों की दोस्ती और मजाकिया अंदाज के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह से शादी की बात कहकर उन्हें कुछ पल के लिए हैरान कर दिया। हालांकि, बाद में आम्रपाली के हंसने से साफ हो गया कि वह यह बात मजाकिया अंदाज में कह रही थीं। आम्रपाली दुबे इन दिनों 'भोजपुरी बवाल' शो में नजर आ रही हैं। शो में उनके साथ दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव भी शामिल हैं। शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इसी बीच वायरल हुए एक वीडियो में आम्रपाली और पवन सिंह के बीच हुई बातचीत ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया।

वीडियो में आम्रपाली गंभीर अंदाज में पवन सिंह से कहती हैं कि

बच्चे को अकेले पालना मुश्किल होता है। इसके बाद वह कहती हैं कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और मिलकर बच्चे की परवरिश करनी चाहिए।

आम्रपाली की यह बात सुनकर पवन सिंह कुछ क्षण के लिए चौंक जाते हैं और उनकी ओर देखने लगते हैं। इसके बाद आम्रपाली हंस पड़ती हैं और पवन सिंह भी मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद आम्रपाली ने पवन सिंह से पूछा कि क्या उन्हें कभी अकेलापन महसूस होता है। उन्होंने कहा कि पवन अच्छे इंसान हैं और दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आम्रपाली ने यह भी कहा कि पवन बच्चों से काफी लगाव रखते हैं और अक्सर उन्हें गोद में उठा लेते हैं।



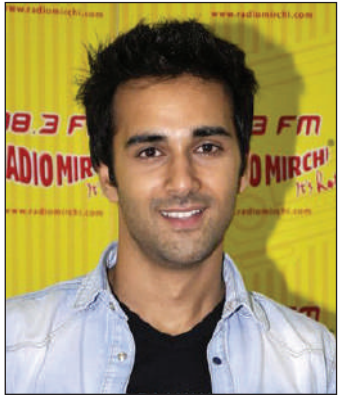
सेल्फी क्वीन निया शर्मा ने रोका कैमरा फेस स्किन ट्रीटमेंट के बाद लिया फैसला

टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री निया शर्मा अपने ग्लैमरस अंदाज और सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर अपनी तस्वीरों और सेल्फी फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं, लेकिन हाल ही में उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस को हैरान कर दिया। निया शर्मा ने ऐलान किया कि वह अगले तीन दिनों तक

सेल्फी नहीं लेंगी। निया के इस अचानक फैसले के बाद उनके फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या वजह है, जिसके कारण अभिनेत्री ने सेल्फी से दूरी बनाने का फैसला किया। निया शर्मा ने क्यों लिया सेल्फी ब्रेक?

रिपोर्ट्स के अनुसार, निया शर्मा ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह कुछ दिनों के लिए फ्रंट कैमरा और सेल्फी से दूरी बनाना चाहती हैं। उन्होंने इसे एक तरह का छोटा ब्रेक बताया। हालांकि, अभिनेत्री ने कोई बड़ी परेशानी या विवाद की बात नहीं कही है। उनका यह फैसला सोशल मीडिया की लगातार भागदौड़ और कैमरे के सामने रहने की आदत से थोड़ा ब्रेक लेने से जुड़ा माना जा रहा है। निया शर्मा के लिए सेल्फी और सोशल

मीडिया अपडेट्स उनके फैंस से जुड़ने का एक बड़ा माध्यम हैं। ऐसे में जब उन्होंने तीन दिन तक सेल्फी नहीं लेने की बात कही तो उनके चाहने वाले हैरान रह गए। कई फैंस ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निया की सेल्फी के बिना तीन दिन बिताना मुश्किल होगा। वहीं कुछ लोगों ने उनके इस फैसले को खुद के लिए समय निकालने वाला अच्छा कदम बताया। निया शर्मा टीवी की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर मजबूत फैन फॉलोइंग है। वह अपने फैशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े पोस्ट शेयर करती रहती हैं। उनका बोल्लड और बेबाक अंदाज अक्सर चर्चा में रहता है।



मलेरिया से जूझ रहे पुलकित

अभिनेता पुलकित सम्राट इस समय मलेरिया से जूझ रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अपनी सेहत से जुड़ा बेबाक अपडेट साझा किया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिकवरी के दौरान की एक तस्वीर शेयर की और बताया कि इस बीमारी ने उनके शरीर पर कितना गहरा असर डाला है, लेकिन वे फिर से अपनी ताकत हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अपनी अनुशासित फिटनेस रूटीन और दमदार फिजीक के लिए पहचाने जाने वाले पुलकित ने बताया कि मलेरिया ने उनके शरीर पर काफी असर डाला है, जिसके चलते न सिर्फ उनका 2.5 किलो वजन (मांसपेशियां) कम हो गया है, बल्कि काफी हद तक ताकत भी चली गई है। हालांकि, इस झटके के बावजूद अभिनेता सकारात्मक बने हुए हैं और अपनी फिटनेस दोबारा हासिल करने के लिए पूरी तरह हढ़ हैं। अपनी रिकवरी का अपडेट शेयर करते हुए पुलकित ने लिखा है, 'मलेरिया ने मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा असर डाला है। 2.5 किलो वजन कम हो गया है और काफी ताकत भी चली गई है। लेकिन मैं इस शरीर को जानता हूँ। हमने इसे पहले भी बनाया है।

टेस्ट क्रिकेट मेरी पहली प्राथमिकता : पडिक्कल

» गॉल, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

श्रीलंका के खिलाफ पहले ही टेस्ट में शतक लगाने वाले भारतीय टीम के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल का लक्ष्य हर अवसर का लाभ उठाते हुए इस प्रारूप में अधिक से अधिक रन बनाकर अपनी जगह पक्की करना है। पडिक्कल को दो साल के बाद टेस्ट टीम में वापसी का अवसर मिला था जिसका उन्होंने पूरा लाभ उठाया। इस बल्लेबाज ने पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 44 रन बनाकर भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अपने प्रदर्शन से उत्साहित पडिक्कल ने स्पष्ट किया कि टेस्ट क्रिकेट उनका अंतिम लक्ष्य है और वे अपने खेल को इसी के अनुसार ढाल रहे हैं। पडिक्कल ने कहा, मैं हमेशा से इस बात को लेकर स्पष्ट रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट मेरा अंतिम लक्ष्य है। इसलिए मैंने अपने खेल को इस तरह ढालने की कोशिश की है कि मैं अपनी बुनियादी तकनीक के साथ खेलते रहूँ। मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि जब भी जरूरत हो मैं लाल गेंद के क्रिकेट में आसानी से ढल सकूँ क्योंकि यह मेरी पहली प्राथमिकता है। पडिक्कल ने हालांकि ये स्वीकार किया कि सीमित ओवरों और टेस्ट क्रिकेट के बीच लगातार बदलाव करना आसान नहीं है, और इसके लिए उन्हें अपनी बल्लेबाजी में सावधानीपूर्वक



बदलाव करने पड़ते हैं। पडिक्कल ने कहा कि प्रारूप के अनुसार वह अपनी बल्लेबाजी को लेकर तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा, सफेद गेंद के क्रिकेट में मेरी बल्लेबाजी की एक अलग तैयारी होती है। इससे मैं अधिक शॉट खेल सकता हूँ और अपने हाथों को थोड़ा खुला रखता हूँ। लेकिन लाल गेंद के क्रिकेट में इस पहलू को थोड़ा कसकर रखना जरूरी है। इसमें हाथ शरीर के कुछ ज्यादा करीब रखने पड़ते हैं।

मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरी पसंदीदा टीम, हालैंड क्रिकेट में भी कर सकते हैं कमाल: रियान पराग

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

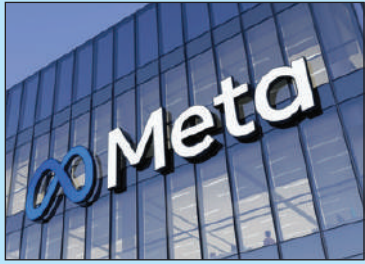
भारत के ऑलराउंडर रियान पराग ने इंग्लिश प्रीमियर लीग की दिग्गज टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अपने गहरे लगाव के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही इस क्लब के प्रति उनके खास लगाव की मुख्य वजह रहे। फुटबॉल के 2026-27 सीजन की शुरुआत से पहले 'जियोस्टार' से बात करते हुए पराग ने कहा, 'जब फुटबॉल की बात आती है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही मेरी टीम है। मैं उन्हें खेलते हुए और उनके खिलाड़ियों को पसंद करते हुए बड़ा हुआ हूँ। मुझे उनकी लाल जर्सी बहुत पसंद थी, और उस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे। यही वजह है कि मैंने इस टीम को चुना।' रोनाल्डो के प्रति अपने लगाव के बारे में विस्तार से बताते हुए पराग ने कहा, 'मैंने हमेशा एक खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया है और वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। जिस तरह से वे कम उम्र में स्पॉटिंग सीपी से आए, फिर प्रीमियर लीग में जो कमाल किया और लीग का स्तर ऊंचा उठाया, मुझे नहीं लगता कि कोई और खिलाड़ी उनके आसपास भी है।'



बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों को लेकर अमेरिकी सीनेटर ने मेटा पर उठाए सवाल

» वाशिंगटन, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

अमेरिकी सीनेटर मार्क वॉर्नर ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग से उन पेड विज्ञापनों को लेकर जवाब मांगा है, जिनमें कथित तौर पर बाल यौन शोषण सामग्री (चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल) शामिल थी। वॉर्नर ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए उस पूर्व जांच का भी हवाला दिया, जिसमें भारत में इंस्टाग्राम पर इसी तरह के विज्ञापन चलने का मामला सामने आया था। अमेरिकी सीनेटर मार्क वॉर्नर ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से उन पेड विज्ञापनों को लेकर जवाब तलब किया है, जिनमें कथित तौर पर



बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) और बिना सहमति के बनाए गए अंतरंग चित्र (एनसीआईआई) शामिल थे। वॉर्नर ने सवाल उठाया कि क्या मेटा ने ऐसे विज्ञापनों से आर्थिक

लाभ भी कमाया।

वर्जीनिया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर वॉर्नर ने 18 अगस्त को भेजे गए एक पत्र में कहा कि मेटा ने अपनी विभिन्न सोशल मीडिया सेवाओं पर ऐसे विज्ञापनों को चलने दिया, जिनमें बाल यौन शोषण सामग्री और गैर-सहमति वाले अंतरंग चित्र शामिल थे। उन्होंने पत्र में लिखा, 'यह पूरी तरह अस्वीकार्य है कि इस प्रकार की सामग्री मेटा के प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि आपकी कंपनी इससे लाभ कमाती हुई प्रतीत होती है।'

वॉर्नर ने मेटा से पूछा कि ये विज्ञापन उसकी समीक्षा प्रणाली से कैसे गुजर गए, कंपनी को इनसे

कितनी आय हुई और इस तरह की सामग्री की पहचान कर उसे हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए। उन्होंने 26 अगस्त तक जवाब देने की समयसीमा तय की है।

सीनेटर ने टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट (टीटीपी) की एक शोध रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके अनुसार मेटा ने नौ महीने की अवधि में फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और थ्रेड्स पर एआई से निर्मित बाल यौन शोषण सामग्री वाले दर्जनों पेड विज्ञापन चलाए। शोधकर्ताओं को मेटा की सार्वजनिक विज्ञापन लाइब्रेरी में बच्चों के शोषण से संबंधित 50 से अधिक तस्वीरों और वीडियो वाले विज्ञापन मिले।

संक्षिप्त खबरें

हवाई द्वीप पर हरिकेन 'लाला' की वजह से 17,000 घरों में छाया अधेरा

लॉस एंजिल्स, यूटर्न/ 20 अगस्त । अमेरिका में हवाई द्वीप के दक्षिण छोर पर स्थित सदरन काउंटी डिस्ट्रिक्ट हरिकेन 'लाला' को गुजरे कई दिन बीत चुके हैं, इसके बाद भी लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सदरन काउंटी के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोग अब भी कीचड़, बड़े पत्थरों और सड़कों पर गिरे पेड़ों की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। स्थिति यह है कि हवाई द्वीप पर लगभग 17,000 घरों में अभी बिजली गुल है। हवाईयन इलेक्ट्रिक ने एक अपडेट में बताया कि ओआहू में प्रभावित 99 प्रतिशत, माउई में 98 प्रतिशत तथा हवाई द्वीप में 75 प्रतिशत ग्राहकों की बिजली बहाल कर दी गई है।

यूएई ने जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के साथ सभी व्यापारिक और वित्तीय संबंध तोड़े

तेहरान, यूटर्न/ 20 अगस्त । संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से जुड़े जहाजों सहित खाड़ी क्षेत्र में मालवाहक जहाजों पर हुए ईरानी हमलों के बाद यूएई ने ईरान से अपने सभी व्यापारिक और वित्तीय संबंध निलंबित कर दिये हैं। यूएई विदेश मंत्रालय के रणनीतिक संचार विभाग की निदेशक आफरा अल हामेली ने बुधवार को घोषणा की कि बढ़ते तनाव के बीच ईरान से सभी व्यापारिक, वाणिज्यिक और वित्तीय लेनदेन को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। अबू धाबी ने तेहरान पर समुद्री यातायात की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइलों दामने का आरोप लगाया, जबकि तेहरान ने इन आरोपों को निराधार बताया है। यह कदम दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को बड़ा झटका देगा, क्योंकि अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद दुर्बल लंबे समय से ईरान के लिए प्रमुख वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र रहा है।



भारत की अफगानिस्तान को मदद जारी, काबुल के हॉस्पिटल को भेजी मेडिकल सप्लाई

काबुल, यूटर्न/ 20 अगस्त । अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने की अपनी पहल जारी रखते हुए, भारत ने गुरुवार को काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयों और मेडिकल सामान की खेप सौंपी। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपने लंबे और भरोसेमंद स्वास्थ्य सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और मेडिकल सामान उपलब्ध कराया है।' यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब भारत लगातार अफगानिस्तान को मानवीय सहायता दे रहा है। इसमें जरूरी दवाइयां, राहत सामग्री और अन्य मदद शामिल है। इस सप्ताह की शुरुआत में नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले एक साल में अफगानिस्तान के साथ भारत की भागीदारी और सहयोग बढ़ा है। इसमें कूटनीतिक बातचीत, मानवीय सहायता और विकास से जुड़े कार्यक्रमों पर खास ध्यान दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत और अफगान लोगों के बीच लंबे समय से गहरे संबंध रहे हैं। पिछले एक साल में अफगानिस्तान के साथ हमारा जुड़ाव और मजबूत हुआ है।'

अमेरिकी नागरिक पर आईसीई एजेंट के बंदूक तानने की घटना के बाद अमेरिकी सांसद ने एफबीआई जांच की मांग की



वाशिंगटन, यूटर्न/ 20 अगस्त । भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम और पांच अन्य अमेरिकी सांसदों ने उत्तरी वर्जीनिया में हुई एक घटना की एफबीआई जांच और न्याय विभाग द्वारा नागरिक अधिकारों की समीक्षा कराने की मांग की है। आरोप है कि इस घटना के दौरान एक आब्रजन (इमिग्रेशन) एजेंट ने एक अमेरिकी नागरिक पर लोडेड बंदूक तान दी थी। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम और पांच अन्य सांसदों ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) के उन अधिकारियों की जांच की मांग की है, जिन्होंने 10 अगस्त को उत्तरी वर्जीनिया के फॉल्स चर्च में कैरोलिना मोलिना की कार को घेर लिया था। सांसदों ने एफबीआई जांच और अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा नागरिक अधिकारों की समीक्षा कराने का अनुरोध किया है तथा न्याय विभाग और होमलैंड सिक्वोरिटी विभाग से 31 अगस्त तक जवाब मांगा है।

एनडीए 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर सीएम सरमा बोले- ऐसा असम बनाना है, जहां महिलाएं बदलाव की अगुवाई करें

» गुवाहाटी, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

असम में एनडीए 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य सेवा पर राज्य सरकार के लगातार फोकस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनडीए 3.0 के पहले 100 दिनों के तहत शुरू की गई पहलों का मकसद एक ऐसा असम बनाना है, जहां महिलाएं बदलाव की अगुवाई करें।

सोशल मीडिया पर अलग-अलग योजनाओं के बारे में बताते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने लिखा कि सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने वाले कार्यक्रमों को मजबूत किया है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया है कि लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आगे बढ़ने के बेहतर मौके मिलें। 'लखीमी मिस्त्री' पहल के तहत, 6,875 से ज्यादा महिलाएं 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (पीएमएवाई-जी) के तहत सर्टिफाइड ग्रामीण राजमिस्त्री (मेसन) बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। इस पहल का मकसद महिलाओं को तकनीकी कौशल और रोजगार के टिकाऊ मौके देना है। साथ ही, ग्रामीण निर्माण कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाना भी है।

सरकार ने 'स्वनिर्भर नारी' योजना के तहत हुई प्रगति पर भी जोर दिया, जिससे 1,051 से ज्यादा बुनकरों और 60 महिला



उद्यमियों को मदद मिली है। कुल 48,338 तय मानकों वाले प्रोडक्ट खरीदे गए हैं और महिलाओं के नेतृत्व वाले रोजगार को मजबूत करने के लिए 1.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

शिक्षा और बाल विवाह की रोकथाम पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। 'निजुत मोइना' योजना के तहत, 2026-27 के दौरान लगभग 5.16 लाख छात्राओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार लगातार शिक्षा को बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने का एक अहम जरिया मानती है।

राज्य ने 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (पीएमएमवीवाई) के तहत माताओं को सीधे आर्थिक मदद देने की बात भी कही। कुल

78,490 योग्य लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) के जरिए 23.26 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे माताओं को मातृत्व के दौरान आर्थिक मदद मिली है।

मुख्यमंत्री सरमा ने माताओं और लड़कियों की स्वास्थ्य सेवा में हुए सुधारों का भी जिक्र किया। असम का 'मातृ मृत्यु अनुपात' (एमएमआर) घटकर 84 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत 87 से कम है। यह पहली बार है जब राज्य का एमएमआर राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। इसके अलावा, 2.94 लाख किशोरियों को टीके लगाए गए हैं, जिससे युवतियों के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं।

जापान में ताकाइची सरकार के खिलाफ जन-आक्रोश, 'इतिहास भुलाने' और 'हथियार-नीति' का विरोध

» टोक्यो, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

टोक्यो में नेशनल डाइट बिल्डिंग (संसद भवन) के बाहर हजारों की संख्या में इकट्ठा लोगों ने ताकाइची सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार इतिहास को भुला सैन्य विस्तार की खतरनाक कोशिश कर रही है।

आयोजकों के मुताबिक, बुधवार शाम को हुए इस प्रदर्शन में करीब 15,000 लोग खुद शामिल हुए, जबकि 25,000 ऑनलाइन जुड़े। रैली में बैनर थामे लोगों ने : 'जो राजनेता युद्ध पर आत्ममंथन करने और जापान के आक्रामकता के इतिहास को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।' प्रदर्शनकारियों ने 'सेना के विस्तार का विरोध करें' लिखे बैनर पकड़े हुए थे और 'शांतिवादी संविधान की रक्षा करें' और 'ताकाइची, अभी पद छोड़ें' जैसे नारे लगाए। सिंहुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जापान की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता मिजुहो फुकुशिमा ने एक इंटरव्यू में कहा कि ताकाइची ने 15 अगस्त को युद्ध में मारे गए लोगों के लिए आयोजित



राष्ट्रीय स्मारक समारोह में अपने संबोधन में जापान के पिछले आक्रामक युद्धों पर 'विचार' करने का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमबारी की याद में आयोजित कार्यक्रमों में देश के 'तीन परमाणु-विरोधी सिद्धांतों' पर ताकाइची की अस्पष्ट टिप्पणियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ताकाइची यह स्पष्ट रूप से बताने में नाकाम रही कि जापान इन सिद्धांतों का पालन करना जारी रखेगा।

उन्होंने कहा, 'यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है।' दक्षिणी द्वीप प्रान्त ओकिनावा के एक प्रदर्शनकारी कियोमासा कोमेसु ने कहा कि ताकाइची सरकार सेना के विस्तार की राह पर चल रही है।

अमेरिका ने बिजली संकट टालने के लिए आपातकालीन अधिकार का किया इस्तेमाल, 65 मिलियन लोगों को मिलेगी राहत

» वाशिंगटन, यूटर्न/ 20 अगस्त ।

ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के मिड-अटलांटिक क्षेत्र में बिजली कटौती का खतरा कम करने के लिए आपातकालीन संघीय अधिकार का इस्तेमाल किया है। यह इलाका 13 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में करीब 6.5 करोड़ लोगों को बिजली सप्लाई करता है। ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बुधवार को स्थानीय समय के अनुसार फेडरल पावर एक्ट की धारा 202(सी) के तहत यह आपात आदेश जारी किया।

इसके तहत मैरीलैंड में स्थित एक पावर यूनिट को निर्धारित सीमा से ज्यादा चलाने की इजाजत दी गई है, ताकि बढ़ती बिजली मांग को पूरा किया जा सके। आदेश के मुताबिक पीजेएम इंटरकनेक्शन, टैलन एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर मैरीलैंड के एनी अरुंडेल काउंटी में वागनर जनरेटिंग स्टेशन की यूनिट 4 को संचालित करेगा। पीजेएम मिड-अटलांटिक क्षेत्र में बिजली सप्लाई को समन्वित करने वाली क्षेत्रीय ट्रांसमिशन संस्था है।



पीजेएम ने संघीय हस्तक्षेप की मांग की थी क्योंकि उसे ज्यादा मांग वाले समय में इस यूनिट की जरूरत पड़ने की उम्मीद है।

क्रिस राइट ने कहा, '6.5 करोड़ अमेरिकियों के लिए बिजली की कमी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मिड-अटलांटिक क्षेत्र में पहले के आदेशों से लाइट चालू रखने में मदद मिली है और मुझे भरोसा है कि यह आदेश आने वाले महीनों में भी ऐसा ही करेगा।'